[श्री भूपेंद्र नारायण मंडल]

कि जो हमारे पार्लियामेन्टरी मंत्री यहां पर हैं, उनको अगर इस बारे में जानकारी हो, तो वे ही जवाब दे दें और न हों तो फिर वे इस बारे में कंसल्ट करके जवाब दें।

घटना यह है कि 24 तारीख को श्री परिमल दास, जो जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय में एक प्रोफेसर हैं, वे पासपोर्ट लेने के लिये रीजनल आफिस में गये और वहां पर उन्होंने क्लर्क को हिन्दी में पासपोर्ट लेने के लिये दरख्वास्त दी। क्लर्क ने उस दरख्वास्त को लौटा दिया और कहा कि हिन्दी में यहां पर दरख्वास्त नहीं ली जाती है। उन्होंने जब अर्जी लेने के लिये इनसिस्ट किया तो क्लर्क ने कहा कि अगर ऊपर के आफिसर कह देंगे तो हम ले लेंगे। इस पर वे रीजनल आफिसर के पास गये और उसने भी उनसे वही बात कही कि यहां पर हिन्दी में दरख्वास्त लेने का सिस्टम नहीं है, इसलिये हम हिन्दी में दरख्वास्त नहीं ले सकते हैं। लेकिन वैसी इनसिस्ट करने के बाद उन्होंने ले ली, लेकिन उनका जो एटीट्यूड था वह घृणा वाला और अवज्ञा का एटीट्यूड था। वहां पर इस तरह का जो व्यवहार एक प्रोफेसर के साथ किया गया, उसके खिलाफ क्या कार्यवाही होगी, यह मैं नहीं कह सकता हूं। इसलिये मैं हाउस का ध्यान इस बात की ओर खींचना चाहता हूं कि आजादी के 26 वर्ष के बाद भी हिन्दुस्तान के नागरिकों को अंग्रेजी में ही दरख्वास्त देने के लिये कम्पेल किया जाता है। हम समझते हैं कि यह भारत सरकार की नीति के खिलाफ बात है। इसलिये मैं चाहता हूं कि सरकार को इस सम्बन्ध में अपनी नीति को स्पष्ट करना चाहिये कि उसकी इस सम्बन्ध में क्या नीति है। सरकार से हम इसका जवाब चाहते हैं।

MR. DEPUTY CHAIRMAN : The House stands adjourned till 3 P.M.

The House then ad ourned for lunch at twentyfive minutes past one of the Clock.

The house reassembled after lunch at three of the Clock, MR. DEPUTY CHAIRMAN in the Chair.

THE PROHIBITION OF BIGAMOUS MARRI AGES BILL, 1970—*contd.*

MR. DEPUTY CHAIRMAN : fs there anybody who wants to speak on this BiH ?

SHRI MOHAMMED USMAN ARIF (Rajasthan) : Yes, I want to speak.

डिपुटी चेयरमैन साहब, मैं इस बिल की सख्त मुखालिफत करता हूं। हमको यह देखना है कि मर्द औरत के जिन्सी ताल्लुकात आजादाना हों या पाबन्दी कानून के जरिये से यानी शादी ब्याह से। इस बिल में यह चाहा जाता है कि मेरिज एक से ज्यादा दो, तीन, चार औरतों से न की जाये। लेकिन अफसोस तो यह है कि अगर आजाद तौर पर मर्द और औरत के जिन्सी ताल्लुकात कायम हों और मर्द और औरत रजामन्द हों तो उस पर किसी किस्म की पाबन्दी नहीं है। चुनाचे लोग आपस में एक दूसरे की रजा और रगबत से चाहे जैसे जिन्सी ताल्लुकात पैदा कर लें और इसकी मिसालें हमारे यहां मुकाबले-तन कम और दूसरे मगरबी मुमालिक की वह लातादाद सोसाइटीज हैं, वो क्लब्स हैं, इशरतखाने हैं, बड़े-बड़े होटल हैं, मखसूस इलाके और बाजार हैं, जहां गर्ल फ्रेंडस्, काल गर्ल्स सप्लाई की जाती हैं और खुल्लम खुल्ला औरतें और मर्द आपस में अपनी रजा और रगबत से जिन्सी ताल्लुकात पैदा करते हैं, इस बदकारी पर किसी किस्म का ऐतराज और रोकथाम नहीं। मगरबी मुमालिक की यह तहजीब मानी जाती है और मगरबी मुमालिक वाले इसको शायस्तगी और कलचर में दाखिल करते हैं। मगर हमारे हिन्दुस्तान में अलग-अलग मजहबों के आला असूलों की वजह से यह सूरतेहाल यानी बे रोकटोक जिनाकारी की वह आम फिजा नहीं जो मगरबी मुल्कों में है। इस्लामी कानून में अगर एक से ज्यादा औरतों से शादी करने की साफ वजह यह है कि सोसाइटी में बिगाड़ न पैदा

हो और जिन्सी तौर पर अगर लोग एक से ज्यादा शादियों के तलबगार हों तो वे जाबते में रह कर शादियां कर लें और आवारगी, बदकारी और जिना की जिन्दगी बसर न करें। यह हमारे हिन्दुस्तान की भी कदीम तहजीब और परम्परा रही है और इस पर हमको बराबर नाज रहा। लेकिन मौजूदा दौर ऐसा बिगड़ा कि रोशनख्याल लोग रोशनख्यालों के पर्दे में यह चाहते हैं कि कानून और जाब्ते के मुताबिक तो एक ही शादी हो, एक औरत से हो, लेकिन आवारगी के दरवाजे उनके लिये खुले रहें। हबसकारी चाहे जितनी औरतों से करें और वह आम तौर पर बिना रोकटोक बदकारी की जिन्दगी बसर करें, इस पर हमें गौर करना है। मैं अर्ज करूं कि इस्लाम में एक से ज्यादा शादियों की जो इजाजत ह, मजबूरी नहीं है। इस्लामी कानून कतई एक मजहबी कानून है। मैं हाउस के मेम्बरान की तवज्जो इस तरफ दिलाना चाहता हूं कि इस बात में हम मुसलमान सभी तरह कुरान के ताबे हैं और कुरान शरीफ को हम आसमानी और खुदाई किताब मानते हैं। हम उसमें किसी किस्म की तबदीली नहीं चाहते और न चाह सकते हैं। इस मामले में मुसलमान बहुत ज्यादा हस्सास, बहुत ज्यादा जज्बाती भी हैं, ऐसा कहने में मुझे कोई बात नहीं है।

अगर हिन्दुस्तान के कुछ नाम निहाद रोशनख्याल मुसलमानों की तरफ से कोई आवाज भी उठाई जाती है तो वह किसी तरह की सनद नहीं हो सकती है। मैं समझता हूं कि उन्होंने इस्लाम को सही नहीं समझा है। उनके खिलाफ मुल्क के कोने-कोने में लाखों मुसलमानों के जलसे हुये हैं और इस्लामी कानून में किसी किस्म की भी तबदीली लाने पर सख्त एहतराज हुआ है। एक से ज्यादा औरतों से शादी करने के बारे में आज भी पाबन्दी है और वह पाबन्दी यह है कि उसी सूरत में एक से ज्यादा शादी की जा सकती है, जबकि शादी करने वाला पूरे इंसाफ से काम ले सके। यह शर्त इतनी कड़ी है कि कोई शख्स एक से ज्यादा औरतों से शादी कर ही नहीं सकता न हिन्दुस्तान के गरीब मुसलमानों की माली हालत ऐसी है। अगर हिन्दुस्तान की हालत देखी जाये और आंकड़े देखे जायें तो लाखों में एक मिसाल ऐसी मिलेगी जहां एक से ज्यादा शादियां की गई हों। एक से ज्यादा औरतों से शादी की ही नहीं जाती। यह बात आम तौर पर गैर-मुस्लिमों के लिये भी कही जा सकती है। जब ऐसी कोई बात ही नहीं है तो इस बहाने से यह कहना कि मुसलमान औरतों पर मुजालिम होते हैं और हम उनके फायदे के लिये ऐसी बात करते हैं और कुछ मुसलमान फर्जी नरकीयाफ्ता औरतें यह कहें भी कि हमारे साथ जुल्म होता है तो मैं यह मानने के लिये तैयार नहीं हूं। शादियां एक से ज्यादा औरतों के साथ करने का आंकड़ा बहुत ही कम है। ऐसी सूरत में मैं यह अर्ज करूंगा कि इस हाउस में तमाम मेम्बरान से यह अपील करूंगा कि इस बात में बड़े धीरज से, सोच विचार से काम लें। यह मसला इतना आसान नहीं है जितना समझ रहे हैं। जैसा कि मैंने अभी अर्ज किया था यह मामला मजहबी जजबात का है, ईमान का जजबा है। इस सिलसिले में मैं कह देना चाहता हूं कि इसमें दखल देने से इन्कलाब और इन्तेशार के खतरात लाहक हो सकते हैं। जिन-जिन ममालिक का हवाला दिया जाता है और यह दलील दी जाती है कि मुसलमान ममालिक में काफी तब्दीलियां आ गई हैं, मैं इस सिलसिले में अर्ज कर देना चाहता हूं कि यह सही नहीं है। वह इस्लामी शरियत के दायरे में रह कर की गई है।

हमारे यहां मुस्लिम ज्यूरिसप्रूडेंस में चार स्कूल आफ थाट्स हुये हैं— पहला इमाम आबू हनीफा, दूसरे इमाम सफाई, तीसरे इमाम हम्मबल और चौथे इमाम मालिक का। ये चार ऐसे स्कालर गुजरे थे, जिन्होंने इस्लाम के ज्यूरिसप्रूडेंस और इस्लामी फिकाह के उसूल बाकायदा मुरत्तब किये थे। उनमें आपस में कई मसायल पर कहीं-कहीं इखतेलाफ है, लेकिन जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं उनके अन्दर कोई इखतेलाफ नहीं है। कुरान के सिलसिले में कोई इखतेलाफ नहीं। जो चीजें बहुत एख्तिलाफी थीं उनको ठीक करने के लिये मुस्लिम मुमालिक में जिन-जिन लोगों ने जहां-जहां

श्री [मुहमद उसमान]

उसकी तरमीम चाही कर ली। जो तबदीली आई है वह कुरान और शरीयत के और सुन्नत के मुताल्लिक आई है। लिहाजा यह जो मिसाल दी जाती है कि मुस्लिम मुमालिक में ऐसा हो गया, यह गलत है। उसके आगे मैं अर्ज करूंगा कि अगर खुदा न खास्ता किसी मुस्लिम मुल्क में, एक या दो में अगर कोई ऐसी तबदीली आई है तो वह हमारे मुल्क के लिये कोई मिसाल नहीं हो सकती और बिलखुसूस उस सूरत में जब कि कुरान और हदीस का इत्तबा हम पर लाजिम है और अगर हम उससे हटते हैं तो वह बात हमारे ईमान तक पहुंचती है। ऐसी सूरत में हमें बहुत गौर और फिक्र करनी चाहिए।

उसके अलावा मैं अर्ज करूं कि एक से ज्यादा औरतों से शादी करने में बड़ी हिकमतें मसलेहतें भी हैं। वह हिकमतें यह हैं कि बेवा औरतें जिनसे शादी नहीं की जाती, उसके सिलसिले में इजाजत होने से बेवा औरतों का मसला हल हो जाता है, उन गरीब और नादार, यतीम औरतों का मसला हल होता है, जिनसे शादी करना शान समझी जाती है, वार के जमाने में जब मर्दों की तादाद कम हो जाती है और औरतें ज्यादा हो जाती हैं तो एक से ज्यादा औरतों से शादी करने से उन को शादियां करने में मदद मिलती है और हमारे मोआशरे और निजाम में कोई गड़बड़ी पैदा नहीं होती। इसके अलावा जैसा मैंने अर्ज किया था कि बगैर किसी पाबन्दी के, शर्त के बगैर शादी के जब किसी औरत से ताल्लुकात पैदा किये जाते हैं तो उनकी वजह से बड़ी गड़बड़ी होती है। और जिनाकारी की जिन्दगी बसर होती है और समाज में उनकी कोई पूछ नहीं होती। बदकार जोड़े के आपस में मुहं काला करने के बाद जो बच्चे उनके मेलजोल से पैदा होते हैं, उनके नान नफके परवरिश, तालीम की जिम्मेवारी उसको पैदा करने वाले बाप पर किसी तरह आयद नहीं होती। उन औरतों की बाद में जो दर्दनाक हालत होती है किसी से छुपी नहीं। नाजायज बच्चों और बदकार औरतों का एक अलग तबका सोसाइटी में पैदा हो जाता है। जिससे नये-नये मसले पैदा हो जाते हैं। जो बच्चे शादियों से पैदा होते हैं उनकी परिवरिश का निजाम कायम रहता है और उनकी वजह से सोसाइटी में इन्तेशार पैदा नहीं होती। इस्लामी कानून में तबदीली से हमारी कौमी यकजहती को भी नुकसान पहुंचेगा। गम और गुस्से के साथ एहसास होगा। हम लोगों का अपना पर्सनल लॉ है, उसमें मदाखलत की कोशिश की जा रही है। मुसलमानों को मजलूम होने का अहसास हो सकता है या दिलाया जा सकता है। इस सिलसिले में मैं अर्ज करूं कि सियासतदां क्या बात नहीं कर सकते, कुछ सियासी पार्टियां यह हवा फैला सकती हैं और कुछ फैला भी रही हैं कि गवर्नमेंट का मंसा सही नहीं है। इलेक्शन की गर्ज से एक नये तरीके का स्टंट पैदा किया जा सकता है और दरअसल किया जा रहा है। और इतनी बड़ी आबादी मुसलमान, जो हिन्दुस्तान में सबसे बड़ी अकलियत है और दस करोड़ है उनके दरमियान और यहां की दूसरी कौमों के दौरान दरम्यान एक आपसी झगड़ा और फसाद पैदा किया जा सकता है। इस हालत को मद्दे-नजर रखते हुये मैं अर्ज करूंगा कि जिन साहब ने यह बिल रखा है वह या तो इसको वापस लें, विद ड्रा करें वरना मैं अर्ज करूंगा कि तमाम मेम्बरान इस बिल को अपोज करें और इसको पास न होने दें।

شری ایم۔ اسعد مدنی۔ (اتر پردیش):

صدر محترم۔ ابھی میرے ایک ساتھی نے جس بل کے بارے میں کہا میں اس کو اپوز کرنے کے لئے کھڑا ہوا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں۔ کہ ہمارے ملک میں ہمارے ملک کے بسنے والوں میں ایک دوسرے کو سمجھنے میں بہت سی غلط فہمیاں راستے میں حائل ہیں۔ وہ صحیح بات کی پوری طرح سے واقفیت نہ ہونے کی وجہہ سے صحیح کام نہیں کر سکتے ہیں۔ ہندوستانی مسلمان جس پوزیشن میں ہیں اس کو صحیح طرح سے سمجھا جائے تو بہت سی غلط

ہو جاتی ہیں ۔ اس لئے ہمارے ملک میں جس چیز کا وجود ہی نہیں اس کے لئے یہ واویلا کیوں ۔ کہیں زیادہ قتل پایا جاتا ہے چوریاں پائی جاتی ہیں ۔ ریپ اور زنا پایا جاتا ہے اور طرح طرح کی برائیاں پائی جاتی ہیں اور کم سے کم کئی کئی شادیوں کی بات اس سے بہت کم ہندوستان کے مسلمانوں میں پائی جاتی ہے اس کا بلا وجہ حوا بنانا اور اس کے لئے اس طرح سے غلط طریقہ پر پروپیگنڈا کرکے بلا وجہہ ہم کو ایک نکو بنانا ہے کہ ہم میں اس طرح کا رول اور رسم پایا جاتا ہے جس کو بدلنے کے لئے کوئی قانون یا بل لانے کی ضرورت ہے یہ ایک غلط قسم کا جذبہ ہے ۔ ہمارا معاشرہ نہ اس چیز کا عادی ہے اور نہ ہندوستان میں یہ چیز عام طور پر پائی جاتی ہے ۔ اس لئے آپ کس چیز کو روکنے کے لئے چلے ہیں جو ہم میں نہیں ہے ۔ میں آپ سے کہتا ہوں کہ عورتیں ہماری بہنیں ہیں ہماری مائیں ہیں ہماری بیٹیاں ہیں صرف بیویاں نہیں ہیں ۔ معاف کیجئے ہم کو عورتوں کی اور ماں بہنوں کی عزت اور آبرو ان کی زندگی ان کو پھلتا پھولتا دیکھنا بہت زیادہ عزیز ہے اپنی زندگیوں کی طرح سے ۔ اس لئے ایسی کوئی بات نہیں ہے ۔ لیکن دوسری طرف ہمارے معاشرہ کا حال کیا ہے ہماری سرکار کی غلط روی کی وجہہ سے ۔ ہمارے ماحول میں عام چیزیں ہیں اور وہ جس طرح پو بڑھ رہی ہیں آج سینیما سے آج فحش تصویر سے ۔ جس طرح سے چوری ڈکیتی بڑھ رہی ہے ۔ چھوٹے فہمیوں سے بچا جا سکتا ہے ۔ در حقیقت ہمارے مذہب میں اسلام میں کئی شادیوں کی صرف گنجائیش ہے ۔ نہ کوئی ترغیب دی گئی ہے نہ کوئی حکم دیا گیا ہے ۔ اور اس کے ساتھہ دوسری شادی پہلی بیوی کی موجودگی میں اگر کی جائے تو اس کے لئے پابندیاں ہیں اور ذرا ذرا سی چوک پر بہت سخت نظر رکھی گئی ہے اور سخت قسم کے حکم عاید کئے گئے ہیں ۔ لگائے گئے ہیں ۔ تو دوسری شادی کرنا یا کوئی شادی کرنا مذہبی اعتبار سے ایک سخت کام ہے آسان اور سہل کام نہیں ہے ۔ شادی کرنے کا جو کوئی شوق ہو سکتا ہے اس سے زیادہ اس میں دقتیں اور پریشانیاں ہیں اس لئے یہ تصور کرنا کہ اسلام میں کئی کئی شادیوں کی ترغیب دی گئی ہے یہ غلط خیال ہے ایسا نہیں ہے۔ صرف گنجائش ہے اس سے زیادہ اس میں اور بات نہیں ہے ۔ اور جہاں تک ہندوستانی مسلمانوں کا تعلق ہے ہمارا معاشرہ تہزیب کلچر جس طرح کا بنا ہوا ہے اس میں دوسری شادی بالکل معیوب ہے اور قطعی اس کا رواج نہیں ہے ۔ اگر گورنمنٹ مردم شماری کرائے اس بات کا پتہ لگائے تو شاید ہندوستانی مسلمانوں میں ہزار میں سے ایک دو فیملیاں بھی ایسی نہیں نکلینگی جنہوں نے کئی کئی شادیاں کر رکھی ہیں ۔ اس طرح کا عام ماحول ہے اور مرد بھی اور عورتیں بھی کئی کئی شادیوں کے لئے قطعی تیار نہیں ہوتیں اور اس کو بہت معیوب سمجھا جاتا ہے ۔ اس طرح خاندان ٹوٹ جاتے ہیں ۔ زندگیاں تلخ

روکیں جو کئی قسم کے عیب برائیاں اور برباد کرنے والی چیزیں آج پھیل رہی ہیں اور ملک کے گوشہ گوشہ میں پھیلائی جا رہی ہیں ان کے اصلاح کی کوشش کریں - تعلیم کو ٹھیک کریں - ایسے قدم اٹھائیں کہ ہمارا معاشرہ ٹھیک ہو پاک ہو - اس طرح کی فضول کی اور فرضی چیزیں کھڑی کرکے ہوا بنانا اس سے کوئی چیز حاصل ہونے والی نہیں ہے - یہ صرف پولیٹیکل گیم ہے یہ بتانے کے لئے کہ فلاں پارٹی یہ کر رہی ہے وہ کر رہی ہے حقیقتاً ان کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے - یہ بالکل فرضی باتیں ہوا میں پھیلائی جارہی ہیں - مسلمان اس سے پاک ہے- مجھے امید ہے آپ حضرات اس غلطفہمی سے نکلیں گے اور اس طرح کی غلط باتوں کو پوری طرح سے اپوز کریں گے-

انہیں باتوں کو کہتے ہوئے میں اس کی سخت مخالفت کرتا ہوں -

†[श्री एम० असग्रद मदनी (उत्तर प्रदेश): सदर मोहतरम, अभी मेरे एक साथी ने जिस बिल के बारे में कहा मैं इसको अपोज करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मैं समझता हूं कि हमारे मुल्क में, हमारे मुल्क के बसने वालों में एक दूसरे को समझने में बहुत सी गलतफहमियां रास्ते में हाइल हैं। मैं सही बात को पूरी तरह से वाक्फियत न होने की वजह से सही काम नहीं कर सकते हैं। हिन्दुस्तानी मुसलमान जिस पोजीशन में है उसको सही तरह से समझों जाये तो बहुत सी गलतफहमिया से बचा जा सकता है। दरहकीकत हमारे मजहब में इस्लाम में कई शादियों की सिर्फ गुंजाइश है न कोई तरगीब दी गई है, न कोई हुक्म दिया गया है। और इसके साथ दूसरी शादी पहली बीवी की मौजूदगी में अगर की जाये तो इसके लिये पाबंदिया हैं और जरा-जरा सी चूक पर बहुत सख्त नजर रखी गई है और सख्त किस्म के हुक्म आयद

†[] Hindi translation

[شری ایم اسد مدنی]

چھوٹے بچوں کا جیب کاٹنا مرڈر کرنا طرح طرح کی چیزیں بڑھ رہی ہیں صرف چند پیسہ کمانے کے لئے تاکہ سنیما کی کمپنیی والے لکھپتی ہو جائیں وہ پیسہ کمائیں اور گورنمنٹ کو زیادہ ٹیکس ملے تمام آپ معاشرہ کا عیب دار بنایا جا رہا ہے - چور بن رہے ہیں اور ڈاکو بن رہے ہیں ان چیزوں کو روکا نہیں جاتا ان سے ہماری لڑکیوں کی نسل اور عورتوں اور بچوں کی زندگیاں تباہ ہو رہی ہیں اور لاکھوں برباد ہو رہی ہیں اور خودکشی کرتے ہیں لڑکے اور لڑکیاں اور تمام اپنی زندگیاں برباد کر بیٹھے ہیں وہاں ہماری قوم کی کوئی ہمدردی نہیں ہوتی اور اس طرف کوئی اقدام نہیں ہوتا اور اس طرح سے فرضی منصوبہ کرکے صرف مسلمانوں کو نکو بنانے کے واسطے غلط چیز کا پروپیگنڈا کرکے اس طرح کا ایک بل پیش کرکے آپ جو کرنا چاہتے ہیں وہ واقعہ کے خلاف ہے - میں احتجاج کرتا ہوں کہ مسلمانوں کو اس طرح بدنام کیوں کیا جاتا ہے اس ہاؤس میں اس طرح کی باتیں کرنے کی کیوں اجازت دی جاتی ہے - ہندوستانی معاشرہ اس سے بالکل پاک ہے - ہم نہیں جانتے کہ پاکستان میں کیا ہوتا ہے اور دوسرے ملکوں میں کیا ہوتا ہے -

ہندوستانی مسلمان جس ماحول میں جی رہا ہے اس کے اندر اس طرح کی باتیں نہیں پائی جاتیں - میں گورنمنٹ سے کہتا ہوں ان کو اس طرف توجہ کرنی چاہئے کہ تمام خرابیوں کو

किये गये हैं लगाये गये हैं। तो दूसरी शादी करना या कोई शादी करना मजहबी एतबार से एक सख्त काम है, आसान और सहल काम नहीं है। शादी करने का जो कोई शौक हो सकता है इससे ज्यादा इसमें दिक्कतें और परेशानियां हैं, इसलिये यह तसव्वर करना कि इस्लाम में कई-कई शादियों की तरगीब दी गई है यह गलत खयाल है, ऐसा नहीं है। सिर्फ गुंजाइश है इससे ज्यादा उसमें और बात नहीं है। और जहां तक हिन्दुस्तानी मुसलमानों का ताल्लुक है, हमारा मुआशरा तहजीब कल्चर जिस तरह का बना हुआ है उसमें दूसरी शादी बिलकुल मायूब है। और कतई इसका रिवाज नहीं है। अगर गवर्नमेंट मरदम शुमारी करायें, इस बात का पता लगायें तो शायद हिन्दुस्तानी मुसलमानों में हजार में से एक दो फैमिलियां भी ऐसी नहीं निकलेंगी। जिन्होंने कई कई शादियां कर रखी हैं। इस तरह का आम माहौल है और मर्द भी और औरतें भी कई-कई शादियों के लिये कतई तैयार नहीं होतीं और इसको बहुत मायूब समझा जाता है। खानदान टूट जाते हैं, जिन्दगियां तलख हो जाती हैं, इसलिये हमारे मुल्क में जिस चीज का वजूद ही नहीं उसके लिये यह बाबेला क्यों? कहीं ज्यादा कत्ल पाया जाता है, चोरियां पाई जाती हैं, रेप और जना पाया जाता है और तरह-तरह की बुराइयां पाई जाती हैं और कम से कम कई-कई शादियों की बात इससे बहुत कम हिन्दुस्तान के मुसलमानों में पाई जाती हैं, इसका बिला वजह हव्वा बनाना और इसके लिये इस तरह से गलत तरीके पर प्रोपेगण्डा करके बिला वजह हमको एक नक्कू बनाना है कि हममें इस तरह का रिवाज और रस्म पाया जाता है, जिसको बदलने के लिये कोई कानून या बिल लाने के जरूरत है, यह एक गलत किस्म का जज्बा है। हमारा मुआशरा न इस चीज का आदी है और न हिन्दुस्तान में यह चीज आम तौर पर पाई जाती है। इसलिये आप किस चीज को रोकने के लिये चले है जो हममें नहीं है? मैं आपसे कहता हूं कि औरतें हमारी बहनें हैं, हमारी मायें हैं, हमारी बेटियां हैं सिर्फ बीवियां नहीं हैं। माफ कीजिये हमको औरतों की और मां बहिनों की इज्जत और आबरू, उनकी जिन्दगी उनको फलता फूलता देखना बहुत ज्यादा अजीज है अपनी जिन्दगियों की तरह से। इसलिये ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ हमारे मुआशरा का हाल क्या है, हमारी सरकार की गलत रवि की वजह से। हमारे माहौल में तमाम चीजें हैं और वे जिस तरह से बढ़ रही हैं आज सिनेमा से, आज फेहश तस्वीर से, जिस तरह से चोरी डकैती बढ़ रही हैं। छोटे-छोटे बच्चों का जेब काटना, मर्डर करना तरह-तरह की चीजें बढ़ रही हैं सिर्फ चन्द पैसे खाने के लिये ताकि सिनेमा की कम्पनी वाले लखपती हो जायें, वे पैसा कमायें और गवर्नमेंट को ज्यादा टैक्स मिले। तमाम आपका मुआशरा ऐबदार बनाया जा रहा है, चोर बन रहे हैं और डाकू बन रहे हैं इन चीजों को रोका नहीं जाता, इससे हमारी लड़कियों की नस्ल और औरतों और बच्चों की जिन्दगियां तबाह हो रही हैं और लाखों बरबाद हो रही हैं और खुदकशी करते हैं लड़के और लड़कियां और तमाम अपनी जिन्दगियां बरबाद कर बैठे हैं, वहां हमारी कौम की कोई हमदर्दी नहीं होती और इस तरह कोई इकदाम नहीं होता और इस तरह से फर्जी मनसूबा करके सिर्फ मुसलमानों को नक्कू बनाने के वास्ते गलत चीज का प्रोपेगण्डा करके इस तरह का एक बिल पेश करके आप जो करना चाहते हैं, वह वाकया के खिलाफ है। मैं एहतजाज करता हूं कि मुसलमानों को इस तरह बदनाम क्यों किया जाता है इस हाउस में इस तरह की बातें करने की क्यों इजाजत दी जाती है। हिन्दुस्तानी मुआशरा इससे बिलकुल पाक है। हम नहीं जानते कि पाकिस्तान में क्या होता है और दूसरे मुल्कों में क्या होता है। हिन्दुस्तानी मुसलमान जिस माहौल में जी रहा है उसके अन्दर इस तरह की बातें नहीं पाई जातीं। मैं गवर्नमेंट से कहता हूं उनको इस तरफ तवज्जह करनी चाहिये कि तमाम खराबियों को रोकें जो कई किस्म के ऐब बुराइयां और बर्बाद करने वाली चीजें आज फैल रही हैं और मुल्क के गोशा-गोशा में फैलाई जा रही हैं उनके इस्लाह की कोशिश करें। तालीम को ठीक करें—ऐसे कदम उठायें कि हमारा मुआशरा ठीक हो, पाक हो। इस तरह की फजूल की और फर्जी चीजें खड़ी करके हव्वा बनाना इससे कोई चीज हासिल होने वाली नहीं है।

[श्री एम० असग्रद मदवी]

यह सिर्फ पोलिटिकल गेम है, यह बताने के लिये कि फलां पार्टी यह कर रही है वह कर रही है। हकीकतन उनका इससे कोई ताल्लुक नहीं है यह बिल्कुल फर्जी बातें हवा में फैलाई जा रही हैं। मुसलमान इससे पाक हैं। मुझे उम्मीद है कि आप हजरात इस गलतफहमी से निकलेंगे और इस तरह की गलत बातों को पूरी तरह से अपोज करेंगे। इन्हीं बातों को कहते हुये मैं इसकी सख्त मुखालफत करता हूं।]

SHRI HAMID ALI SCHAMNAD (Kerala) : Mr. Deputy Chairman, Sir under Muhummudan law marriage is a social contract and under the Hindu law marriage is a sacrament. As far as Muhammadari law is concerned it is a social contract just as we make any other social contracts between two parties. If the girl is a minor, then the father of the girl gives his daughter to a person who is willing to take her in marriage with two witnesses thereof. This is the simple formality. As far as the Muhammadan law is concerned, the Muhammadan law imposes many conditions if anyone wants to marry more than one. It is not correct to say that a Muslim cannot marry as many wives as he wants. It is also not correct to say that there are no conditions. He can marry more than one only on one condition. Only if he can fulfil that condition can he marry more than one. Prophet himself has imposed the condition that a man who cannot maintain one wife cannot marry more than one. By 'maintaining" not only financial maintenance is meant but also it is necessary to impart affection equally. If a person marries two wives he has to maintain them, look after them mentally, physically and in alJ aspects equal treatment should be given. Prophet himself has said that it is generally difficult to look after more than one but at the same time if a person feels that he can marry two or three and look after them with fullest satisfaction then there is no objection to his marrying them. In India we Muslims have been permitted under the Shariat law to follow our own personal law. In spite of the licence given to them may I ask you, Sir, what is the percentage of Muslims today who marry more than one? Take any State, Kerala, Mysore or U.P. or anywhere; what is the percentage of Muslims who make use of this licence? It is only very few, not even five per cent, not even one per cent I should say, who think that they can marry more than one according to the canon of the law. So it is not correct to bring a law to compel the Muslims who want to marry more than one not to do that and to deprive them of their chance. Our friends from the other side say Pakistan has got a law and they have amended the Shariat law and so on. It is not correct. What Pakistan has done or what many of the Muslim countries have done is that they have constituted a court to find out whether a Muslim who wants to marry more than one satisfies the conditions and the criteria imposed by the Prophet. He goes through those conditions. For example, if I am not able to maintain my wife and children, I have no right to marry again and have a second wife. Whatever court is constituted, it has to go through these facts and find out whether the criteria have been implemented. Now, if we accept this Bill, it will only affect the sentiments and feelings of the Muslim minorities of India. I appeal to the Mover of this Bill not to press it in the interests of the minority community, in the interests of this community which has been given freedom to choose its own faith, to profess, propagate and carry on its religion. Now, one may ask what religion has got to do with marriage. Is it not the personal right of a person? It is not correct as far as Islam is concerned. We cannot bifurcate personal fife from religion. Religion does not mean only going to mosque and praying. Every walk of life of a person is closely connected and clubbed with religion. I cannot marry as 1 like. There is a prohibition for me to marry anybody I like. Religion commands me that I should marry only certain persons.

SHRI SARDAR AMJAD ALI (West Bengal) : He said something about pro-

hibition, that I cannot marry the girl 1 desire according to my view.

SHRI HAMID ALI SCH\MNAD : My friend can marry anybody. I have no objection.

SHRI SARDAR AMJAD ALI : He said something about religious porhibi-tion.

SHRI HAMID ALI SCHAMNAD : I, as a Muslim, cannot marry a prostitute. Religion says you should not marry so and so. A Muslim cannot many, lor example, his sister's daughther or niece. A Muslim is prohibited from marrying his sister's daughter, but there are other sections or communities where it is permitted. This prohibited degree comes in in the case of a Muslim. Also, a Muslim cannot marry a non-Muslim. That is also there, j

SHRI SARDAR AMJAD ALI : This is a wrong interpretation.

MR. DEPUTY CHAIRMAN : You can take your turn and speak after him.

SHRI SARDAR AMJAD ALI : I am not going to speak.

MR. DEPUTY CHAIRMAN ; Clarification you can seek when you speak.

SHRI SARDAR AMJAD ALI : If my friend says that I am prohibited from marrying a prostitute, I believe this is not a true picture I can marry a prostitute provided she accepts my religion. If she goes through the religious part, I can do it.

SHRI HAMID ALI SCHAMNAD : Anyhow, he wants that the prostitute to be converted to his religion. I have no objection. Only I say about the prohibited degree. Every religion has got its own prohibited degree. So, my submission is that after all the percentage of Muslims who marry and have more than one wife is much less. It is not such a problem in this land. We have got many other problems to be tackled. By bringing forward this legislation we will be only offending the feelings of this community.

SHRI AWADHESHWAR PRASAD SINHA (Bihar) : Mr. Deputy Chairman, Sir, 1 have read the Statement of Objects and Reasons. Mr. Sen Gupta says that polygamy is practised by the people of several other communities in India. This discrimination should go and polygamy should be prohibited for all. The Bill seeks to achieve this object. Mr. Sen Gupta is an enthusiastic youngman and perhaps he does not realise the texture of the Indian society. It is a mosaic made of many communities and many religions. What may be good for one religion may not be good for another. If it is generally accepted that one should have only one wife, it is easier to deal with one, but it all depends on the man's vitality, virility and also financial ability. We do not want to stand in the way of these youngmen. Very soon I am going to reach the Biblical age of three scores and ten.

So, I do not bother. I am a widower, and I am going to end my life like that. If my friend, the poet—Shri Arif—wants to please himself, we are not going to grudge it. Why should Shri Sen Gupta grudge it? I do not understand it. So, to my friends who are there, 1 should like to say—what ever the composition of this House, this great House is a House of elders. But never do anything which goes against the sentiments, the religious feelings of any religion or any community. The Muslims are a big chunk. The Parsis are a very small community in this country, the Jews are a very small community. We will never do anything which will go against their religion or against their accepted principles. So, we should try to understand him also. Some of my young friends have spoken very vigorously about it. I would like that they should understand Shri Sen Gupta also. He is a very progressive gentleman, he believes in things. But he should realise—in his enthusiasm, he should not go beyond a certain point. And that is the mistake of the youth. I also did it when I was a youth.

SHRI BRAHMANANDA PANDA t (Orissa) : I think it is a confession.

SHRI AWADHESHWAR PRASAD SINHA.: I love him very much. He is a very desirable sort of man. But the Bill of his is not a desirable one. That is all I can say. We should know how to differn-tiate between a person and what the person says. So, we should not wax eloquent on this. And I would beg of my Muslim friends sitting here, sitting in the Opposition, sitting in the other House and in the country, anywhere, that any Congressman will be the last man to do anything which mitigates against the sentiments of my Muslim friends or any other minority in this country.

SHRI JAGDISH PRASAD MATHUR (Rajasthan) : My friend just spoke about Pakistan and some other Muslim countries where they have got some tribunal which operates this Muslim law and sees that anyone who wants to marry a poor lady is fulfilling the conditions or not. What happens in Pakistan, Turkey and such countries, can that not be applicable in India also by law ? Is he agreeable to that proposal ?

MR. DEPUTY CHAIRMAN : Mr. Schamnad, I permit you to reply if you want.

SHRI HAMID ALI SCHAMNAD : My friend has asked rrv.' about the law in Pakistan. I can only say that we are a minority in India. Pakistan did not do anything with the law of the minorities. After all, they are in a majority. Here we are not in a majority. As a majority, they can afford to do that. We are not following Pakistan.

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI BEDABRATA BARUA) : I am grateful to the Members who have participated, and also I thank the Mover for throwing some light on this question which has been repeatedly raised before the House. Government also has made its position clear several times in reply to various questions.

Sir, this Bill seeks to prohibit bigamous marriages between the citizens of India residing in this country and outside. Although its scope looks like being very wide, in real fact, this is a sort of declaratory Bill which wants to make a declaration in cases where a very vast majority of the population of India is already statutorily obliged to have monogamous marriages. It is well known that under the Hindu Marriage Act of 1955 a Hindu cannot legitimately take more than one wife. The definition of "Hindu" is such that it includes all Hindus, including Vaishyas, Lingayats, Brahmans, Arya Samajists, Buddhists, Jains, Sikhs and so on. This Bill would not apply to the Jews, the Christians and the Parsis because they have already got special laws in regard to that. The personal law of the Christians itself enjoins monogamy. So the objective appears to be—in fact, it has been rightly taken also by members of the Muslim community and by others—as an attempted legislation which would concern mainly the Muslims of India. It would have the effect really of altering the existing law of the Muslim community only.

Sir, so far as this Bill is concerned and so far as the Muslim community is concerned I am thankful to the Members for having said this repeatedly—and I do not think there is any division on this point that so far as the Muslim community in India is concerned, this community, by and large, has been overwhelmingly monogamous in character. So far as the Muslim practice in India is concerned, there has been some distinction between the Muslim practice in this country and the various other countries. The Muslim practice here, by and large, is monogamous. So far as the Muslim Koranic injunctions are concerned T think it has been made clear several times—and the hon'ble Minister, Mr. Gokhale, has also explained the position in the last discussion in this House and it has been quoted by the mover from Mr. Abdul Rahim who wrote "The Mohammaden law undoubtedly contem-

plates monogamy as the ideal to be aimed at but it conceded a man the right to have more than one wife, not exceeding four at one and the same time provided he is able to deal with them on a footing of equality and justice". So this is the juridical opinion on the spirit of Mohammaden law . as such.

Sir, in view of the fact that Mohammaden law considers monogamy as the ideal to be aimed at, although it has allowed under special circumstances certain aberrations from that ideal, and in view of the fact that the Muslim community have* by and large, pursued monogamous type of relations so far as marriages are concerned,' this practice is now dying out. This practice of polygamy, which was prevalent throughout the country and amongst the various communities in India including the Hindus, is now dying out due to various ecosomic and other reasons. In view of these factors, I do not think the Government should attempt to force a legislation upon the Muslim community without the consent of the Muslim community as such. The Government had never considered changes in the personal law of a minority community as a matter to be decided without the consent of that community. The Government has consistently been saying in answer to various questions in Parliament that it is the policy of the Government that no change in the personal law of the minorities should be introduced unless the initiative to that change comes from the community concerned. So, Sir, it is not possible at this stage. This initiative has to come from the community itself and the community has to speak out on these matters. We are glad to note that due to various factors this practice is dying out very fast.

Sir, stray cases are there among the Muslims. As Maulana Saheb, Mr. Kasim Ali Abid, Mr. Usman Arif and other Muslim Members said, there are stray cases of polygamy among the Muslims. But, Sir, as Mrs. Lakshmi Kumari Chnndawat said the other day, in spite of the enactment of the Hindu Marriage Act of 1955, in her State polygamy still continues amongst a small section, of the Hindus. In spite of the legislation being on the statute book, it has really made no difference to those who practise polygamy. So, while it is a fact that a very marginal practice of polygamy is there amongst the Muslims as the law has allowed it, a similar practice is also there amongst the other communities in spite of the laws and enactments that have been made against it. Therefore, Sir, in view of the considered opinion given by the leaders of the Muslim community in this House, in the other House and outside in the other platforms, it would serve no useful purpose to say that the Government should make an enactment at this stage when it is not acceptable to the community as such. And the Government does not believe that there is any impelling need or necessity at this stage, and the practice is not of a noteworthy magnitude. The question of a uniform civil code is itself raised before the House sometimes. This is the objective laid down in the Constitution. But this uniformity has to come only by consent. India is a country of varied cultures and people of different religions living together. Our country is a secular State. We believe in the freedom of all religions to pursue their religious practices unhindered by any majority who may try to reform them against their will. So, in this situation it will not be expedient to undertake a legislation for this purpose. and the Government has taken a positive stand on this matter. The Government has no doubt that Muslims are progressively practising monogamy, and the Indian Muslims are not prepared to accept a legislation without proper decisions being made amongst themselves. The Prime Minister has also clarified several times that the Government would never try to impose changes in the Indian Muslim community without the consent of the Muslims and she would not even think of causing injustice to any minority community. So, the Government's position is clear and I have stated it also repeatedly here. Mr. Sen Gupta has also taken a reasonable stand. He said:

(.Shri Bcdabrata Barna]

"If the majority of the Muslims say 'No', I shall most gladly withdraw this Bill. I am not here to impose my views or the views of the Hindu majority or the views of any non-Muslim majority or them . . ."

SHRI DWIJENDRALAL SEN GUPTA (West Bengal): Please read that again. There has been some misunderstanding.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: That is j why he has read it.

SHRI BEDABRATA BARUA: I have quoted him to say that I do not think there would be very much of a difference if I request the hon. Member to withdraw this Bill. I hope he will withdraw this Bill. If he does not find his way to withdraw it, I will be compelled to oppose it in view of the Government policy already stated.

SHRI DWIIENDRALAL SEN GUPTA: Mr. Deputy Chairman, Sir, there is a lot of confusion about the stand taken by me because the House on the 17th August was dull and none of the speakers who spoke to-day was present on that day. They possibly harboured a feeling that it was an anti-Muslim Bill. So...

شري ايم اسعد مدني : هم معذرت كرتے هيں-

†[श्री एम० असग्रद मदनी : हम माजरत करते हैं।]

SHRI DWIIENDRALAL SEN GUPTA: ... possibly they took it upon themselves as a crusade to oppose the Bill. But it is not so. I am here for rousing their conscience. I shall only refer to certain portions from the Synopsis of the debate on the 17th August, which was circulated the following day.

In my speech, I showed due respect for the 'Koran' and the Hadis and, I shall continue to do so. I said, "According to the Koran or the Hadis, a Muslim could marry a second wife only with the consent of the first wife if the first wife has lost the capacity of bearing children or if she was of ill health. But these considerations was not observed in every case." So, I stood by the three rules of Koran- The hon. Minister admits that there are few who are not as religious as the hon'bie friends here are, and what about them? The Muslim personal laws are there. So far as the recalcitrants are concerned, what Is the remedy? That is my question to them. Then again it has been said, and l also said that 'very few Muslims had more than one wife'. One hon'bie Muslim Member said one per cent. I say It may be even less than that. I mentioned that. I did not say that every Muslim had four wives. I do not say that. I said, 'very few have'. Again I am repeating from the synopsis of the Debate of August 17, what I said: "The Bill should be circulated for eliciting public opinion. If the majority of the Muslims replied in the negative, the Member would be prepared to withdraw." So, not today, even on the first day I said: "if the majority of the Muslims do not want", after circulation, I shall withdraw the Bill. So, if they are in majority, the State should pass it. So far as this Parliament is concerned the majority here is the Congress. They cannot support this Bill on the eve of U.P. elections, however, they agree on principle. I know that. So, from the point of timing also I do not expect the support of the Congress nor I desire to impose any law on the minority by votes of majority on any sensitive matter. Having done a mischief so far as the Aligarh Muslim University is concerned, they do not do second mischief and that is wise.

AN HON. MEMBER : They are discouraged.

SHRI DWIIENDRALAL SEN GUPTA: I am sorry. Possibly I have been misunderstood because of the Bill. And I can tell my Muslim friends that I talked to very responsible Muslim M.Ps. before I brought the Bill here. If you want to know the names, I can give the names also. They said, so long as you keep the ideal of the Koran and the Hadis, you can pursue the matter. After discussing the matter

t[ ] Hindi transliteration.

thoroughly with them, I had brought the Bill. And I can tell you that there are many good friends among the Muslims inside the Parliament and outside the Parliament who wanted that the Bill be passed. But at the same time, I was very anxious about the sentiments of the minority community. Now} I would like to throw some more light on it...

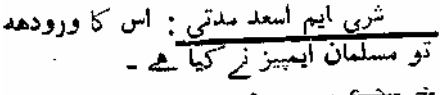

شری ایم اسعد مدنی : اس کا ورودھه تو مسلمان ایمپیز نے کیا ہے ۔

†[श्री एम० असअद मदनी : इसका विरोध तो मुसलमान एम० पीज० ने किया है।]

SHRI DWIJENDRALAL SEN GUPTA: Because I did not have the occasion to talk to you.

Now, there are certain developments. On the 17th of this month, this Bill was discussed in this House. On the 18th, that is, on the next day, a delegation of the Muslim leaders met the Prime Minister, and its news appeared in the Times of India and Indian Express on the 19th. This delegation was led by Sheikh Abdullah and consisted of Mufte Atiqur Rehman, President of the Majlis-i-Islam, Mr. Khalil Ahmed, former Chief lustice of Orissa, and Mr. Bhasin Ahmed, a former Judge. What the report says in this.

"The delegation is understood to have informed the Prime Minister of the fear of the community that the Muslim Personal Law might be changed against its wishes."

I repeat that this fear is wrong. There is no reason to fear that it will be changed against their wishes . . .

MR. DEPUTY CHAIRMAN : Then, do you withdraw the Bill?

SHRI DWIJENDRALAL SEN GUPTA: I made it clear even before they met the Prime Minister. I made it clear on the 17th itself. Had they known it, possibly they would not have met the Prime Minister on 18th. This delegation said—I am reading the Express News Service of 18th August, published in Indian Express on 19th August—

"The delegation suggested to the Prime Minister that the Government should set up some kind of a machinery to ascertain Muslim opinion before laws affecting them were passed."

They named some laws in this connection. I am fully in agreement with this Muslim delegation. They want a machinery to ascertain the opinion of the Muslims. I would have been glad if in consonance with this representation of the Muslim leaders, the Muslim MPs. here, particularly that man with cap—I forgot his name—

AN HON. MEMBER: The honourable Member or the honourable friend.

SHRI DWIJENDRALAL SEN GUPTA : Yes, the honourable Member, my honourable friend, a very good friend, I am sorry I do not know his name—if those MPs. had suggested that. Where is that suggestion from them? Anyway, I say let the suggestion of the Muslim leaders be accepted. Then I have with me a cutting of the Bengali Paper, "Ananda Bazaar Patrika" of 30th August, 1973. It says, last Tuesday there was a conference of the Muslims at the Calcutta Press Club wherein they said two things: There Jahanara Begum said : (in Bengali):

"JAHANARA BEGUM BOLEN, SAMBIDHANER CHODDO-NONG-DHARAR PROTI NAGORIKER SA-MAN ADHIKAR-O-AK-E-INER AOTAI THAKAR JE ADHIKAR ROECHHE, TA MUSHALMAN NARI-DER BAD DIYE NOI. CHURI ITYADI APRADH SANKRANTA IYNER BELAI MUSLIM DHARMA GRANTHER SHARIA-TY IYNE BODLANO JODI SAMBHAV HOI, TAHOLE ONYANYO KHETRE-YO HOTE PARE."

I shall translate it into English. In Shariat there was a particular type of

†[ ] Hindi transliteration.

[Shri Dwijendralal Sen Gupta]

punishment for theft. In Shariat the provision for theft is, if a man steals, his hands will be cut. That is the punishment. But i nobody says that the provision of Shariat] should continue and for theft hands should be cut. For the purpose of marriage they swear in the name of Shariat. Why do you not swear in the name of Shariat in respect of stealing, in respect of adultery, in respect of other vices? Shariat has made provision for punishment in those cases also. There you do not say we shall not go by the Indian Penal Code. Which means you want the best of both worlds. What is advantageous in Shariat, you take it; what is good in the Indian Penal Code, you take that also, however, it is against Shariat. This is an inconsistent attitude . . .

SHRI SIKANDAR ALI WAJD (Maharashtra): Punishment and permission are not same. One is 'shall' and the other is 'may'.

SHRI DWIJENDRALAL SEN GUPTA: Mr. Deputy Chairman, you know Bengali and you must have understood it. For the convenience of other Members I shall translate it into English. She says Article 14 of the Constitution provides for equality and she asks why that equality should be denied to the Muslim women. I am reading the provisions of Article 14 of the Constitution:

> "The State shall not deny to any person equality before the law or the equal protection of the laws within the territory of India".

This lady was taking her stand on this provision of the Constitution.

I am quoting another passage. (The quotation was in Bengali from the speeches of two other speakers in the same meeting) :—

"AMDADUL HAK BOLEN, SAKOL BHARAT BASHIR JONNEY AKI IYNE THAKA DARKAR. ABDUS SAMAD BOLEN, MUSLIM JUVAKDER DESH-BYAPI PRACHARE NAMTE HOBE. RABIUDDIN AHMED BOLEN. BOHU MUSLIM DESHE SHAR1ATHY IYNE BODLE JUGPOJOGY kORA HOE-CHHE."

This is what three Muslim speakers said about this. So, these hon'ble friends are not the only Muslims. There are many Muslims outside the House who have supported me by and large. Many newspapers in editorials supported the cause. There is that support and the concensus is there. I shall only beseech you and through you this House that though they may not pass this Bill—1 am not pressing this Bill—let the Government give an assurance as demanded by the Muslim leaders themselves —say Sheikh Abdulla—that there should be a machinery constituted to ascertain the views of the Muslims themselves in regard to these changes.

My friend over there, Mr. Mathur, asked a question to which Shri Schamnad replied. He said that in Muslim majority countries there may be prohibition. But India being a Muslim minority country, there should be no prohibition or codification. This is no analogy, no reason at all. If there is codification of Shariat laws in Muslim majority countries and Muslims there are not afraid of religion, why not our friends here also fall in line either with >Turky or Pakistan? Turky has completely abolished it. They have banned it. Pakistan and other Muslim countries by codification have controlled it. Whatever it is, let them not forget that the Muslim ladies also deserve some protection. What [said was that polygamy is a social evil and should be ruthlessly suppressed. Is there anybody who thinks that it is not a social evil or is there anybody who thinks that it should not be suppressed? I have not heard anybody saying that. So, the whole House is with me so far as the spirit of the Bill is concerned. Then where do they differ? They differ in a very narrow margin and that narrow margin is about the method. Should there be codification or not because of Shariat? I do not think that because of Shariat or Quoran there should not be codification or that is a bar. But I say it should not be imposed. I do not

like to offend the sentiments of my Muslim brothers. So, I do not press the Bill.

The Bill was, by leave, withdrawn.

THE TRADE UNIONS (AMENDMENT) BILL, 1970

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You may move the next Bill.

SHRI MONORANJAN ROY (West Bengal): I find the Treasury Benches are empty. They are interested only in voting.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Opposition benches are also empty.

4 p. M.

SHRI DWIJENDRALAL SEN GUPTA (West Bengal): Sir, I move:

> "That the Bill further to amend the Trade Union Act, 1926, be taken into consideration."

While moving this Bill, I would like to draw the attention of the House to the Statement of Objects and Reasons.

> "There is no provision for recognition of trade unions in the Trade Unions Act, 1926, or in any other Central Act. As such, the employers often recognise only those trade unions which suit their purpose, irrespective of the representative character of the said trade unions. This Bill seeks to provide for the conditions of recognition as well as to determine the scope and ambit of all such recognised trade unions."

Mr. Deputy Chairman, Sir, the Bill which I am piloting now is just the Bill which was passed by the West Bengal Legislative Assembly during the UF Regime . . .

SHRI MONORANJAN ROY: In 1969.

SHRI DWIJENDRALAL SEN GUPTA: Yes, in 1969. Now, the unfortunate position is that this Bill as passed by the West Bengal Legislative Assembly did not get the assent of the President for reasons unknown. I wanted a certain note from the Research Section of the Parliament and the note reads like this:

> "It is understood from the Government sources that the Trade Unions of West Bengal (Amendment) Bill, 1969, has not been submitted to the President for assent so far. The West Bengal Government have been asked to await Central Legislation on the subject.'"

Sir, this is no compliment for the Central Government if the West Bengal Government had sent it to the Central Government for being placed before the President. It seems that the Central Government has not placed it before the President, because the West Bengal Government has been asked to await Central legislation on this subject. If the West Bengal Government has been asked to await Central legislation on the subject, here is a chance for the Central Government for enacting such a legislation. If they disagree with any of the provisions contained therein, Sir, they can submit their amendments. Instead of rejecting it wholesale, it would be proper for the Government to point out why and what amendments are necessary. But no amendments have been tabled so far.

Mr. Deputy Chairman, Sir, I would like to remind this House that as early as 1947, the Central Legislature passed the Trade Unions (Amendment) Act, 1947 which was not enforced as the said Act was of a far-reaching nature and contained provisions for the compulsory recognition of unions and for penalising anti-labour practices. The reasons for non-enforcement were partly administrative and partly the far-reaching character of the amendments themselves. Many felt that the unions would take years to satisfy the qualifications under the amended Act. There was some opposition even within the Central Government to the enforcement of the amendment. I am giving these details, Sir, from the Report of the National Commission on Labour, 1969 (page 295). Now, as early as